such public sector units ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (c) The C&AG of India report No. (1) & (3) of 1993 contains a para on investment of surplus funds by some public sector undertakings. The PSEs and the administrative Ministries/ Departments concerned look into the specific objections mentioned in the C&AG report and take suitable remedial measures.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यशील पूंजी की कमी

4308. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता का कम उपयोग होने का प्रमुख कारण कार्यशील पूंजी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से कौन-कौन से उपक्रम प्रभावित हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हैं । कुछ सरकारी उपक्रमों के मामले में कार्यचालन पूंजी की कमी इन कारणों में से एक सुसंगत कारण है । क्षमता के कम उपयोग के अन्य कारण हैं—कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, बिजली की कमी, कलपुर्जों की कमी, संयंत्र एवं मशीनों की खराबी तथा निम्न उत्पादकता/क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने यह सूचित किया है कि कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण उक्त अवधि के दौरान उनकी क्षमता उपयोग प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है । इन उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) । कार्यचालन पूंजी के प्रबन्ध का दायित्व मुख्यत: प्रबन्धन का है । अवरोध यदि संसाधन उपलब्ध हो तो सरकार कुछेक सरकारी उपक्रमों को गैर-योजनागत ऋण भी देती है ताकि वे अपने कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें ।

विवरण

1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
2. भारत आप्टोलिक ग्लास लि०
3. एल्गिन मिल्स कंपनी लि०
4. भारतीय उर्वरक निगम लि०
5. भारी इंजीनियरी निगम लि०
6. इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
7. महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
8. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
9. राष्ट्रीय साईसाईकिल निगम लि०
10. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
11. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
12. नेटेका (गुजरात) लि०
13. नेटेका (सतपुड़ा महाराष्ट्र) लि०
14. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा) लि०
15. उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
17. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
18. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित केन्द्र

4309. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में इस समय राज्य-वार और शहर-वार कितने खादी ग्रामोद्योग केन्द्र स्थापित हैं;

(ख) इन केन्द्रों में किस-किस चीज का उत्पादन होता है; इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; इन केन्द्रों में कितने पुरुष कर्मचारी हैं और कितनी महिला कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में कोई धनराशि आबंटित की जा रही है; क्या इन केन्द्रों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और देश में कितने नए केन्द्र खोले जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) के० वी० आई० सी० सीधे पंजीकृत संस्थाओं के जरिये खादी कार्यक्रम चलाती है जबकि ग्रामोद्योग कार्यक्रम मुख्यत: के० वी० आई० बोर्डों द्वारा चलाया जाता है । 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 2353 है । के० वी० आई० कार्यक्रम अनेक सहकारी समितियों द्वारा भी चलाये जाते हैं जिनकी संख्या 29813 है तथा 30 राज्य के० वी० आई० बोर्ड हैं ।

(ख) खादी के अतिरिक्त के० वी० आई० सी० के कार्य-क्षेत्र तथा के० वी० आई० सी० अधिनियम के अधीन आने वाले

ग्रामोद्योगों की संख्या 96 है जिन्हें 7 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है :—

1. खनिज पर आधारित उद्योग ।
2. वन आधारित उद्योग ।
3. कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग ।
4. पॉलिमर तथा रसायन पर आधारित उद्योग ।
5. इंजीनियरी तथा गैर-परम्परा-गत ऊर्जा ।
6. वर्ग उद्योग (खादी के अतिरिक्त) ।
7. सेवा उद्योग ।

वर्ष 1991-92 के अंत तक के० वी० आई० कार्यकलापों द्वारा दिये गये रोजगार की कुल संख्या 50.16 लाख है (खादी—14.20 लाख और ग्रामोद्योग—35.96 लाख) । महिलाओं को दिया गया रोज़गार 23.07 लाख है जो के० वी० आई० सी० द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 46% है ।

(ग) सरकार के० वी० आई० सी० को उनके कार्यकलाप चलाने के लिए अपने वार्षिक बजट में निधियाँ उपलब्ध कराता है ।

के० वी० आई० सी० समय-समय पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करके खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों का विदेशों में निर्यात करने को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है ।

के० वी० आई० सी० देश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रहा है तथा भविष्य में और केन्द्रों के खोले जाने की संभावना है ।

Administrative set up of Small-Scale Industries

4310. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are planning to restructure the administrative set up governing the small-scale sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have any plan to change the legal provision relating to small-scale industrial units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES & AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. However, Govt. is responsive to the developmental needs of small industries and adjusts its regime of administrative systems, rules and procedures in accordance with requirements.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में औद्योगिक कार्यशाला

4311. **श्री बलदेव आनन्द पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्यशाला, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को भारत सरकार से कार्य नहीं मिलने का क्या कारण है;

(ख) क्या भारत सरकार बिहार के लोगों की प्रगति नहीं चाहती है; और

(ग) यदि सरकार बिहार के लोगों की प्रगति चाहती है, तो क्या वह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची स्थित औद्योगिक कार्यशाला को समुचित सहायता देना चाहेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी की कार्यादेश स्थिति संतोषजनक रही है, फिर भी कम्पनी को संसाधनों की कमी और कड़ी प्रतिस्पर्धा आदि जैसे अनेक कारणों से कार्यादेश की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) और (ग) एच० ई० सी० को योजना और गैर योजना निधियों, बैंकों में नकद उधार सीमा बढ़ाकर तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन इत्यादि के द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है ।

Contributory Pension by P.S.Us

4312. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI B. K. HARIPRASHAD:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the proposals of some Public Sector Undertakings for payment of contributory pension to their employees have not been considered by Government;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether some of these undertakings have already collected funds from their employees; and

(d) if so, the names of such Public Sector Undertakings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The Memoranda of Understanding signed by some Public Sector Enterprises dur-